महंगी चीनी से मिलें मालामाल

- नियंत्रण हटाने को हो रहे लामबंद

- सरकार ने उद्योग के समर्थन में उठाए सकारात्मक कदम, उपभोक्ताओं ने चुकाए 10 रुपये प्रति किलो ज्यादा दाम

नई दिल्ली, प्रेट्र : इस साल चीनी उद्योग ने मिठास का खूब स्वाद चखा है। 80 हजार करोड़ रुपये के इस उद्योग के उत्पादन में खासी बढ़ोतरी हुई है। उद्योग ने बड़ी मात्रा में चीनी का निर्यात किया है। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से भी चीनी को नियंत्रणमुक्त किए जाने के संकेत मिले। उद्योग के उलट आम लोगों को पूरे साल चीनी के तकरीबन 10 रुपये प्रति किलो ज्यादा दाम चुकाने पड़े।

ऊंची कीमतों की बदौलत चीनी मिलें किसानों को बीते सत्र (अक्टूबर, 2011 से सितंबर, 2012) में 52,000 करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान और बकाया चुकाने में कामयाब हुई। चीनी उद्योग पर पांच करोड़ गन्ना किसान निर्भर हैं। बीते सत्र के दौरान चीनी का उत्पादन 2.63 करोड़ टन रहा था। इससे पहले वाले वर्ष में चीनी के कुल उत्पादन का आंकड़ा 2.44 करोड़ टन था। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक भारत ने इस साल 34 लाख टन चीनी का निर्यात भी किया। कुछ ऊंची कीमतों और कुछ सरकार के सकारात्मक कदमों से मिलों ने साल भर खासा मुनाफा कमाया।

साल 2012 की शुरुआत इस उद्योग के लिए उम्मीदें लेकर आई। जनवरी में प्रधानमंत्री ने चीनी को नियंत्रणमुक्त करने के लिए सी रंगराजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति नियुक्त की। साल की समाप्ति पर अब उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार उद्योग पर लगे नियंत्रण हटा लेगी। इस समिति ने अक्टूबर में चीनी उद्योग के लिए सकारात्मक सिफारिशें की हैं। इनमें नियंत्रित रिलीज प्रणाली और लेवी चीनी की बाध्यता हटाना शामिल है। लेवी के लिए सस्ते दामों पर सरकार को चीनी मुहैया कराने की वजह से उद्योग को हर साल करीब 3,000 करोड़ रुपये की चपत लगती है। इसके अलावा एक और नियंत्रण गन्ना के दामों का सरकार द्वारा निर्धारण है।समिति की रिपोर्ट आने से पहले अप्रैल में ही सरकार ने हर महीने चीनी का रिलीज कोटा तय करने के बजाय इसे तिमाही कर दिया। खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने उद्योग के प्रतिनिधियों को रंगराजन की सिफारिशें लागू करने का आश्वासन दिया है। कृषि मंत्री शरद पवार पहले से ही इसके समर्थन में हैं। सरकार ने नवंबर में उद्योग के हित में एथेनॉल की कीमत को भी बाजार के हवाले कर दिया। किसानों को भी चीनी की ऊंची कीमतों का फायदा मिला। इसकी वजह से इस साल किसानों का गन्ना मूल्य बकाया घटकर महज 444 करोड़ रुपये रह गया। मिलों की ओर से इस दौरान उन्हें पचास हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया।